

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग

देहरादून दिनांक : 12 जनवरी, 2016

विषय :- युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय परिसर में बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम हॉल/सभागार के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1522/दो-लेखा-2506/2015-16 दिनांक 03.12.15 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय परिसर में बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम हॉल/सभागार के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था के द्वारा प्रस्तुत आगणन ₹ 168.96 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹ 161.86 लाख में से वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-98/VI-2/2014-52(1)14 दिनांक 14.07.14 के द्वारा ₹ 50.00 लाख, शासनादेश संख्या-191/VI-2/2015-51(22)13 दिनांक 25.03.15 के द्वारा ₹ 20.40 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-472/VI-2/2015-51(22)13 दिनांक 31.08.15 के द्वारा ₹ 40.46 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त इसी वित्तीय वर्ष में उपरोक्त निर्माण कार्य की अवशेष एवं अन्तिम धनराशि ₹ 51.00 लाख को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपभोग/व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015, शासनादेश संख्या-645/XXVII(1)/2015 दिनांक 04 जून, 2015, शासनादेश संख्या-1325/XXVII(1)/2015 दिनांक 16 नवम्बर, 2015 तथा शासनादेश संख्या-1336/XXVII(1)/2015 दिनांक 17 नवम्बर, 2015 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।
- कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-5-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।
- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता

परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

10. प्रथम चरण के कार्यों हेतु निर्गत धनराशि में यदि कोई बचत है, तो उसका समायोजन उपरोक्त किश्त से करते हुए अन्तिम किश्त की यू0सी0 समयान्तर्गत उपलब्ध करायी जाए।

11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद स्टेडियम-16-आउटडोर फील्ड, इण्डोर हॉल व मिनी स्टेडियम का निर्माण-00-24-वृहत् निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 07 / VI-2 / 2016-52(1)14, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. महाप्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।